2 पूर्व विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर ED की रेड

5 राजनयिक से लोकसभा अध्यक्ष तक का सफर

7 नेपाल बाढ़ की त्रासदी के व्यापक मायने

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 16 प्रति सोमवार, 7 सितंबर 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

लोहा चोर ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह 'छोटू' पर कसा शिकंजा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

लोहा चोर ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह 'छोटू' पर जीएसटी का शिकंजा कसने के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र से लंबे समय से कथित रूप से हो रही लोहा चोरी को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल चोरी की घटनाओं तक सीमित नहीं हैं। मामला राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, संयंत्र की आंतरिक व्यवस्था, परिवहन तंत्र, सुरक्षा व्यवस्था, कबाड़ की निकासी, खरीददार इकाइयों और पुलिस की कार्रवाई तक पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले करीब 40 वर्षों में संयंत्र से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये मूल्य का लोहा चोरी हो चुका है। इस दावे की वास्तविकता जांच का विषय है, लेकिन यदि इसमें तथ्य है तो यह अपने आप में अत्यंत गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई संगठित तंत्र सक्रिय रहा, तो उसकी पूरी

श्रृंखला अब तक जांच के दायरे में क्यों नहीं आई? क्या पुलिस की जांच केवल चोरी के दौरान पकड़े गए छोटे आरोपियों और वाहनों तक सीमित रही या उन लोगों तक भी पहुंची, जिनके बारे में कथित तौर पर वर्षों से चर्चा होती रही है? सूत्रों का कहना है कि लोहा चोरी से प्राप्त रकम का 04 आईपीएस, 03 आईएएस और 12 राजनेताओं में बंटवारा होता है। इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी अरुणदेव गौतम के समक्ष कई सवाल और जांच के बिंदु रखे गए हैं। मांग की गई है कि मामले को केवल एक सामान्य चोरी के प्रकरण के रूप में न देखते हुए इसकी पूरी आर्थिक और आपराधिक श्रृंखला की जांच की जाए। जीएसटी की जांच के बाद ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई जैसी संस्थाएं भी जांच करें तो और भी कई कारनामें सामने आ जायेंगे।

कटी हुई गाड़ियों का रिकॉर्ड बने जांच की पहली कड़ी,

कथित लोहा चोरी में इस्तेमाल होने वाली 100 से अधिक गाड़ियों को रातों-रात काट दिए जाने का आरोप लगाया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो परिवहन विभाग के अभिलेख इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। जिन वाहनों को काटा गया, उनके पंजीयन, स्वामित्व, फिटनेस, परमिट और अन्य विवरण निकाले जा सकते हैं। इसके बाद यह पता लगाया जा सकता है कि इन वाहनों के मालिक कौन थे, वे किन परिवहनकर्ताओं से जुड़े थे और वर्षों के दौरान इनका उपयोग किन कार्यों में हुआ। गौरतलब है कि इंद्रजीत सिंह ऊर्फ छोटू' को भिलाई के प्रमुख ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में गिना जाता है। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में किसानों को मिला नया संबल

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से लेकर बोनस भुगतान तक, किसानों के हित में कई अहम फैसले

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी कृषि संस्कृति, गांवों और किसान जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और धान उत्पादन के कारण इसे देश-दुनिया में 'धान का कटोरा' भी कहा जाता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक मजबूती केवल खेती-किसानी तक सीमित विषय नहीं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास से जुड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों को केंद्र में रखकर कई ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देना है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सबसे प्रमुख आधार धान खरीदी व्यवस्था रही है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिला। (शेष पेज 3 पर)

मध्यप्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों से फिर गरमाई सियासत

मोहन यादव की कार्यशैली नहीं कर पा रही जनता को प्रभावित

मध्यप्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चाओं का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। मंत्रालय के गलियारों से लेकर भाजपा के संगठनात्मक स्तर तक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और संभावित बदलाव को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, ऐसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मोहन यादव की कार्यशैली प्रदेश की जनता को प्रभावित नहीं कर पा रही है। किसान, युवा, व्यापारी वर्ग सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। खासकर किसान के मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई है। वहीं दतिया उपचुनाव में मिली हार से भी नकारात्मक माहौल बना है। ऐसे में यह सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है कि यदि कभी नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है तो पार्टी की पहली पसंद कौन होगा? अब लंबे समय बाद मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं का फिर उभरना अपने आप में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या मोहन यादव से पार्टी में नाराजगी है?

मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डॉ. मोहन यादव को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष कितना वास्तविक है? (शेष पेज 2 पर)

राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा से लेकर पुलिस, संयंत्र प्रबंधन और प्रभावशाली लोगों की भूमिका तक उठ रहे प्रश्न; क्या इंद्रजीत सिंह ऊर्फ छोटू जैसे लोहा चोर लड़ेंगे विधायक का चुनाव?

(पेज 1 का शेष)
वे हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर हैं और कंपनी करीब 1,500 ट्रकों के संचालन से जुड़ी बताई जाती है।

कबाड़ की निकासी और वजन व्यवस्था पर सवाल

संयंत्र से निकलने वाले कबाड़ और अन्य सामग्री की जांच तथा वजन की व्यवस्था भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। आरोप है कि संयंत्र से बाहर जाने वाली सामग्री के वजन और निगरानी में गंभीर कमियां थीं। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि स्क्रैप की नीलामी और निकासी के समय वजन की क्या व्यवस्था थी, किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी और सुरक्षा जांच किस स्तर पर होती थी।

परिवहन यूनियन और आर्थिक लेन-देन की जांच जरूरी

मामले में परिवहन यूनियन की गतिविधियों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि यूनियन के माध्यम से हर महीने बड़ी राशि की वसूली होती है और इस धन के बंटवारे को लेकर भी सवाल हैं। यदि ऐसा कोई आर्थिक तंत्र मौजूद है तो उसके बैंक खातों, लेन-देन, लेखा दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा सकती है।

राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की भी जांच हो

मामले को लेकर यह आरोप भी लगाया गया है कि कथित रूप से चोरी से अर्जित धन का इस्तेमाल राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने में किया जाता रहा है। कुछ लोगों पर समाजसेवा की आड़ में बड़ी मात्रा में धन खर्च करने के आरोप लगाए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय और संपत्ति में असामान्य अंतर दिखाई देता है तो आय के स्रोत की वैधानिक जांच संबंधित एजेंसियां कर सकती हैं।

राजनीतिक गिरफ्तारी के आरोपों ने बढ़ाई बहस

एक भाजपा मंडल के कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति वैध कर बिल के साथ माल खरीदता था, फिर भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई और मामले को राजनीतिक रंग दिया गया। इस मामले में वास्तविकता जांच के बाद ही सामने आ सकती है। यदि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल राजनीतिक पहचान के आधार पर कार्रवाई हुई है तो यह भी गंभीर विषय होगा।

भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई कब?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई और सुशासन का दावा करती रही है। ऐसे में यदि भिलाई इस्पात संयंत्र से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई में देरी क्यों होनी चाहिए? यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें हैं और जांच में प्रथमदृष्टया तथ्य सामने आते हैं तो सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को साधने में नाकाम मोहन यादव

(पेज 1 का शेष)
राजनीतिक चर्चाओं में कुछ वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के बीच मतभेदों का उल्लेख किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा और नरेन्द्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इन चर्चाओं के साथ जोड़े जा रहे हैं। हालांकि, किसी नेता की सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक निर्णयों पर असहमति या बयान को सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत अथवा नेतृत्व परिवर्तन की मांग मान लेना उचित नहीं होगा। भाजपा जैसे बड़े संगठन में अलग-अलग नेताओं की अपनी राजनीतिक भूमिका और प्रशासनिक प्राथमिकताएं होती हैं। कई बार सामान्य राजनीतिक मतभेदों को भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जाने लगता है। इसके बावजूद यदि संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर लगातार सवाल उठते हैं तो शीर्ष नेतृत्व के लिए यह निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकता है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को हमेशा प्राथमिकता देता रहा है।

कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी बड़ा मुद्दा

राजनीतिक समीकरणों में केवल मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका

महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं का रुख भी काफी मायने रखता है। मध्यप्रदेश भाजपा का संगठन लंबे समय से मजबूत कैडर और बूथ स्तर के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। ऐसे में यदि कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की कोई वास्तविक स्थिति बनती है तो पार्टी संगठन उसे गंभीरता से ले सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं की कथित नाराजगी को व्यापक संगठनात्मक असंतोष मानने से पहले उसके प्रमाण और वास्तविक राजनीतिक प्रभाव का आकलन जरूरी होगा। चुनावी राजनीति में टिकट, पद, स्थानीय नेतृत्व और प्रशासनिक अपेक्षाओं को लेकर असंतोष समय-समय पर सामने आता रहता है।

शीर्ष नेतृत्व के सामने असली चुनौती

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक स्थिरता और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना है। मुख्यमंत्री बदलना केवल किसी एक व्यक्ति को हटाने या नए व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय नहीं होता। इसके साथ मंत्रिमंडल, संगठन, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति जैसे कई पहलू जुड़े होते हैं। मध्यप्रदेश भाजपा के सामने यदि नेतृत्व परिवर्तन का कोई विकल्प कभी आता है तो उसे यह भी देखना होगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल की राजनीतिक स्वीकार्यता क्या है और बदलाव का चुनावी लाभ कितना मिल सकता है। बिना स्पष्ट राजनीतिक लाभ के नेतृत्व परिवर्तन करना पार्टी के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है।

केन्द्रीय नेतृत्व की निगाहों में प्रदेश की हलचल

मौजूदा स्थिति को 'नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर चल रही राजनीतिक चर्चा' के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। आने वाले दिनों में भाजपा संगठन की गतिविधियां, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और वरिष्ठ नेताओं के बयानों पर राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी। यदि पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक संकेत सामने आता है तो वर्तमान चर्चाओं को नई दिशा मिल सकती है। तब यह साफ होगा कि मध्यप्रदेश भाजपा केवल राजनीतिक अटकलों के दौर से गुजर रही है या वास्तव में प्रदेश के नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला आकार ले रहा है। फिलहाल मध्यप्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है क्या यह केवल सत्ता के गलियारों में उठी अफवाहों की लहर है या भाजपा के भीतर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट? इसका जवाब आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।

महिला नेतृत्व की चर्चा ने बढ़ाया सस्पेंस

प्रदेश में महिला चेहरे का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कृष्णा गौर का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कृष्णा गौर का नाम फिलहाल अटकलों के दायरे में ही है।

पूर्व विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर ED की रेड

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। NHAI के टोल प्लाजा पर कथित फर्जी टोल वसूली और रकम की हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ED की टीमों ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में एक साथ करीब 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इसी कार्रवाई के तहत ED की टीम ने नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा स्थित पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के हाईवे स्थित कार्यालय पर भी छापेमारी की। खबर के मुताबिक संजय शर्मा की कंपनी के पास नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का काम होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी के अनुसार, टोल वसूली में कथित तौर पर अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर फर्जी टोल रसीदें तैयार करने की आशंका है। आरोप है कि टोल से वसूली गई राशि के एक हिस्से को NHAI के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर डायवर्ट किया गया। ED की जांच में फॉरेंसिक परीक्षण और NHAI के रिकॉर्ड के आधार पर कथित अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात सामने आने का दावा किया गया है। एजेंसी कथित फर्जीवाड़े से जुड़े पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। बताया गया है कि इस मामले में ED की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, NCR और कोलकाता समेत विभिन्न स्थानों पर तलाशी ले रही हैं। तेंदूखेड़ा और देवरी स्थित कार्यालयों में भी अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है।

गीता निकेतन को-एड स्कूल में हर्षोल्लास से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। गीता निकेतन को-एड स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भक्तिमय एवं रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर नन्हे-मुन्ने विद्यार्थी श्रीकृष्ण एवं राधा के मनमोहक स्वरूप में सजकर विद्यालय पहुंचे। बच्चों ने सुंदर वेशभूषा के साथ भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को प्रस्तुत किया। विद्यालय में मटकी सजावट, मटकी फोड़, नृत्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और पूरा विद्यालय परिसर कृष्णमय हो गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती निशा पाटीं एवं डायरेक्टर गणेश पाटिल का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिकाओं वंशिका, वंदना, अनन्या, अनामिका, रूपाली, भारती, पूजा एवं हर्षाली सहित समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में ग्रामीण स्वच्छता को मिल रही नई गति

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में रायगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 2,495 पात्र ग्रामीण परिवारों के घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) निर्माण के लिए 299.40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पहल ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ओडीएफ प्लस गांवों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की सुविधा मिलने से ग्रामीण परिवारों को घर पर ही सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होगा। इससे खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के साथ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित होगा। स्वच्छता की यह सुविधा ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।

ओडीएफ प्लस रायगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

जिले में 2,495 परिवारों को शौचालय सुविधा मिलने से स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रामों के निर्माण को गति मिलेगी। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के साथ स्वच्छ, सुंदर एवं ओडीएफ प्लस रायगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से लेकर बोनस भुगतान तक, किसानों के हित में कई अहम फैसले

(पेज 1 का शेष)

यह निर्णय उस सोच को सामने लाता है जिसमें किसान को केवल उत्पादनकर्ता नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार माना गया है।

भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे किसान

धान खरीदी की यह व्यवस्था किसानों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, कृषि उपकरण, सिंचाई और श्रम पर होने वाले खर्च के बीच उपज का उचित मूल्य किसान की आय और आर्थिक स्थिरता तय करता है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर खरीदी से बाजार की अनिश्चितता कम होती है और किसान अपनी उपज को लेकर अधिक भरोसे के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार ने किसानों के खाते में पिछली सरकार के दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी अंतरित किया। 3,716.38 करोड़ रुपए के बोनस भुगतान से बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक राहत मिली। यह राशि केवल लंबित भुगतान की पूर्ति नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे पूंजी के प्रवाह का माध्यम भी बनी। किसान के हाथ में पैसा पहुंचने से खेती की अगली तैयारी, कृषि निवेश, घरेलू जरूरतों और स्थानीय बाजार में खर्च बढ़ता है। इसका सीधा असर गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

व्यापार और उद्योग को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच में किसान और गांव प्रदेश की विकास यात्रा के केंद्र में हैं। उनका मानना है कि जब किसान खुशहाल होगा, तभी गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इसका लाभ व्यापार तथा उद्योग को भी मिलेगा। यही कारण है कि कृषि को केवल एक विभागीय विषय के रूप में देखने के बजाय इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखने पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण हरेली तिहार है। सावन माह की अमावस्या के अवसर पर मनाया जाने वाला यह पर्व किसानों और कृषि जीवन के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। हरेली के दिन किसान अपने कृषि औजारों- हल, कुदाली, फावड़ा, गैती और अन्य उपकरणों की पूजा करते हैं। पशुधन को नहलाया जाता है और अच्छी फसल तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। हरेली में कृषि और प्रकृति के बीच छत्तीसगढ़ के पारंपरिक संबंध भी दिखाई देते हैं। पशुधन को औषधीय सामग्री खिलाने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि ग्रामीण समाज ने सदियों से खेती के साथ पशुपालन और स्थानीय वनौषधियों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। गांवों में यादव समाज द्वारा वन क्षेत्रों से लाई जाने वाली जड़ी-बूटियों को किसानों तक पहुंचाने की परंपरा सामाजिक सहयोग की भावना को दर्शाती है। इस पर्व से जुड़ी गेड़ी की परंपरा भी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति की पहचान है। बच्चे और युवा हरेली के अवसर पर गेड़ी चढ़कर उत्सव मनाते हैं। कृषि औजारों की पूजा, पशुधन के प्रति संवेदना, पारंपरिक व्यंजन और सामुदायिक आयोजन इस पर्व को केवल धार्मिक उत्सव नहीं रहने देते, बल्कि इसे किसान जीवन और ग्रामीण सामाजिक समरसता का उत्सव बना देते हैं।

ग्रामीण अर्थतंत्र होगा मजबूत

सरकार की किसान हितैषी नीतियों का महत्व इसी व्यापक संदर्भ में समझा जा सकता है। किसान की आय मजबूत होगी तो ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे गांव के छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर और स्थानीय व्यवसाय भी लाभान्वित होंगे। कृषि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से ग्रामीण बाजार मजबूत होंगे और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। इस तरह किसान को मजबूत करने वाली नीति का प्रभाव खेत से निकलकर पूरे ग्रामीण आर्थिक तंत्र तक पहुंचता है।

समर्थन मूल्य पर खरीदी किसानों को लाभ

धान खरीदी और बोनस भुगतान के साथ किसान सम्मान का भाव भी सरकार की नीति में दिखाई देता है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि किसान को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले और उसे अपनी उपज के मूल्य को लेकर अनिश्चितता न रहे। समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था इसी भरोसे को मजबूत करती है। वहीं लंबित बोनस का भुगतान किसानों के प्रति सरकार की जवाबदेही को भी रेखांकित करता है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह भी जरूरी है कि खेती को परंपरा के साथ आधुनिक जरूरतों से जोड़ा जाए। कृषि उपकरणों की पूजा करने वाली संस्कृति आज आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। बदलते समय में सिंचाई, बेहतर बीज, कृषि यंत्रीकरण, बाजार तक पहुंच और उत्पादन की लागत कम करने वाले उपाय किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार के सामने आने वाले समय में यही चुनौती और अवसर दोनों हैं।

आर्थिक संबल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की किसान केंद्रित नीतियों को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिले और किसान अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त हो। धान खरीदी की मजबूत व्यवस्था, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा और हजारों करोड़ रुपए के बोनस भुगतान जैसे फैसलों ने किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल, किसान की खुशहाली का अर्थ केवल खेत में बेहतर फसल नहीं है। इसका अर्थ है- परिवार के बच्चों की बेहतर शिक्षा, घर की जरूरतों की पूर्ति, कृषि में दोबारा निवेश, स्थानीय बाजार में बढ़ती गतिविधियां और गांवों में आर्थिक आत्मविश्वास। किसान मजबूत होता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो प्रदेश के विकास की नींव और अधिक मजबूत होती है। हरेली तिहार इसी किसान केंद्रित सोच का सांस्कृतिक प्रतीक है। जिस दिन किसान अपने हल और कृषि औजारों की पूजा करता है, पशुधन के स्वास्थ्य की कामना करता है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसी दिन यह भी याद आता है कि प्रदेश की समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को आर्थिक संबल देने के प्रयास इसी भावना को नीतिगत आधार देने का प्रयास हैं।

सम्पादकीय

सड़कों पर उतरता मध्यप्रदेश और सवालों के घेरे में व्यवस्था

मध्यप्रदेश में इन दिनों सड़कों पर उतरते लोगों की तस्वीरें बार-बार सामने आ रही हैं। कभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रोजगार की मांग लेकर धरने पर बैठे दिखाई देते हैं, कभी वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक किसी नए आदेश के विरोध में प्रदर्शन करते हैं और कभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काम बंद करने का रास्ता अपनाते हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार नागरिकों की ताकत है, लेकिन जब किसी व्यवस्था में अपनी बात कहने के लिए बार-बार सड़क का सहारा लेना पड़े, तो यह केवल आंदोलन का विषय नहीं रह जाता, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सबसे अधिक चिंता शिक्षा के क्षेत्र को लेकर उभर रही है। जिस विद्यालय में शिक्षक होना चाहिए, वहां शिक्षक के बजाय रिक्त पद और इंतजार दिखाई दे तो उसका असर सीधे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। दूसरी ओर, योग्य और चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा में आंदोलन करने को विवश हों, तो यह स्थिति और अधिक विडंबनापूर्ण हो जाती है। यह सवाल केवल शिक्षक या शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं का नहीं है। इसके केंद्र में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य है। यदि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, तो कितनी भी योजनाएं, डिजिटल सुविधाएं और भवन निर्माण के दावे किए जाएं, शिक्षा की गुणवत्ता का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। इसलिए शिक्षक भर्ती को केवल रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया मानना उचित नहीं होगा। यह प्रदेश के भविष्य में निवेश का विषय है। विरोध का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन के सामने आने वाली हर मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता। वित्तीय सीमाएं, नियम-कायदे और प्रशासनिक प्राथमिकताएं अपने स्थान पर हैं। लेकिन असहमति का समाधान दमन या टालने से नहीं, संवाद से निकलता है। यदि कोई निर्णय हजारों कर्मचारियों या अभ्यर्थियों को प्रभावित करता है तो उसके पीछे की वजह स्पष्ट रूप से बताना, उनकी आपत्तियां सुनना और समयबद्ध समाधान की दिशा में आगे बढ़ना सरकार की जिम्मेदारी है।

लगातार आंदोलन यह संकेत भी देते हैं कि शासन और समाज के बीच संवाद के स्थापित मंच पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं। यदि प्रतिनिधिमंडल मिलने के बाद भी महीनों तक उत्तर नहीं मिलता, ज्ञापन के बाद भी निर्णय नहीं होता और आश्वासन की समय-सीमा समाप्त हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष सड़क पर आता है। यही असंतोष धीरे-धीरे अविश्वास में बदल सकता है। मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह स्थिति नीति-निर्माताओं के लिए आत्ममंथन का अवसर है। हर आंदोलन को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में देखने के बजाय उसके पीछे छिपे कारणों को समझना जरूरी है। शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, अतिथि शिक्षकों की चिंता हो, परीक्षा और भर्ती से जुड़े प्रश्न हों या कर्मचारियों की सेवा संबंधी मांगें- इन सभी में एक साझा तत्व दिखाई देता है, वह है अपने भविष्य और अधिकारों को लेकर असुरक्षा। सरकार के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही होगा कि वह लंबित मामलों की प्राथमिकता तय करे, विभागवार समय-सीमा निर्धारित करे और उसकी सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध कराए।

सड़क लोकतंत्र की अंतिम आवाज नहीं, बल्कि संवाद का एक चेतावनी संकेत है। जब विद्यालय छोड़कर शिक्षक सड़क पर आते हैं, जब नौकरी की आस लगाए युवा धरने पर बैठते हैं और जब कर्मचारी काम रोककर अपनी बात कहते हैं, तब केवल नारों को नहीं, उन नारों के पीछे की बेचैनी को सुनने की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश के विकास की वास्तविक कसौटी केवल नई परियोजनाएं और बड़े निवेश नहीं, बल्कि यह भी है कि उसके नागरिकों को अपनी जायज बात रखने के लिए कितनी बार सड़क पर उतरना पड़ता है। लोकतंत्र में सरकार और जनता आमने-सामने खड़ी शक्तियां नहीं हैं। दोनों एक ही व्यवस्था के दो पक्ष हैं। इसलिए जरूरी है कि आंदोलन समाप्त कराने से अधिक महत्व उस कारण को समाप्त करने को दिया जाए, जिसने आंदोलन को जन्म दिया। यही रास्ता शिक्षा को मजबूत करेगा, युवाओं का विश्वास बढ़ाएगा और शासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह तथा सहभागी बनाएगा।

सियासी गहमागहमी

युवाओं से संवाद के जरिए कांग्रेस की हुंकार

मध्यप्रदेश में कांग्रेस अब युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में है। 'युवाओं से संवाद' कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी युवा वर्ग की समस्याओं, अपेक्षाओं और भविष्य से जुड़े सवालों को उठाते हुए सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस अभियान को युवाओं की आवाज को राजनीतिक मंच देने के अवसर के रूप में देख रही है। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा, महंगाई और अवसरों की कमी जैसे मुद्दे युवाओं के बीच चर्चा के केंद्र में हैं। कांग्रेस का प्रयास है कि संवाद के जरिए युवाओं को संगठन से जोड़ा जाए और उनकी नाराजगी को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। आने वाले समय में यह अभियान प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है।

क्या मोदी फिर सौंपेंगे मप्र की जिम्मेदारी शिवराज को?

मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि क्या भाजपा नेतृत्व भविष्य में शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप सकता है? फिलहाल शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिवराज का मध्यप्रदेश की राजनीति में लंबा और प्रभावशाली अनुभव रहा है। वे करीब डेढ़ दशक तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भाजपा को राज्य में मजबूत राजनीतिक आधार देने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विदिशा से उनकी बड़ी जीत ने भी उनके जनाधार को रेखांकित किया। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच शिवराज का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आता है। हालांकि अभी इसे राजनीतिक संभावना से अधिक कयास ही माना जाना चाहिए। भाजपा में अंतिम निर्णय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति पर निर्भर करता है। फिर भी यदि भविष्य में प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ मिलता है, तो 'मामा' की वापसी का सवाल मध्यप्रदेश की राजनीति में सबसे दिलचस्प चर्चाओं में शामिल रहेगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

सोचिए, ऐसा क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने कि इन्हें गोली मार दी गई?

इन्होंने सरकार से सिर्फ तीन चीजें माँगी थीं - शिक्षा, रोजगार, और जवाबदेही।

एक छात्र के पैर की हड्डी AK 47 की गोली से टूट गई। सेना में जाकर देश की सेवा करने का उसका सपना भी उसी के साथ चला गया। दो और छात्रों के कंधों को गोली चीरती हुई निकल गई।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

इंदौर में गूँजेगी छात्रों की आवाज़!

नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के छात्र संवाद के तहत 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित "छात्रों की गूँज" कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

राजनयिक से लोकसभा अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुकी हैं मीरा कुमार

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनकी पहचान केवल उनके पदों से नहीं, बल्कि उनकी सहजता, विनम्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से बनती है। मीरा कुमार ऐसा ही एक नाम हैं। देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल करने वाली मीरा कुमार ने राजनयिक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व में राजनीति के साथ साहित्य, संस्कृति, खेल और सामाजिक सरोकारों का भी सुंदर समन्वय दिखाई देता है। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार में बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के परिवार में हुआ। उनके पिता जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के प्रमुख राजनेताओं में रहे और देश के उप प्रधानमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। राजनीतिक विरासत वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद मीरा कुमार का शुरुआती झुकाव सीधे राजनीति की ओर नहीं था। उन्होंने शिक्षा को अपने व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनाया। उनकी शिक्षा विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज तथा मिरांडा हाउस से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर तथा कानून की शिक्षा हासिल की।

शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा का रास्ता चुना। वर्ष 1973 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित होने के बाद उन्होंने विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्पेन, ब्रिटेन और मॉरीशस में राजनयिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और प्रशासन का व्यापक अनुभव मिला। कई भाषाओं पर उनकी पकड़ ने भी उनके व्यक्तित्व को अलग आयाम दिया। हालांकि विदेश सेवा में सफल करियर के बावजूद उनके भीतर समाज और देश के व्यापक सरोकारों से सीधे जुड़ने की इच्छा प्रबल होती गई। यही इच्छा उन्हें राजनीति में ले आई। वर्ष 1985 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लोकसभा उपचुनाव जीतकर संसदीय राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के करोलबाग और बिहार के सासाराम से भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उनके राजनीतिक जीवन में उतार-चढ़ाव भी आए, चुनावी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। संगठन में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं और वे कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य तथा पार्टी महासचिव जैसे पदों पर रहीं।

वर्ष 2004 में सासाराम से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मीरा कुमार को केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इस भूमिका में सामाजिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दे उनके कार्यक्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। राजनीति में उनकी पहचान एक गंभीर, अध्ययनशील और संयमित नेता के रूप में मजबूत होती गई। उनके सार्वजनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वर्ष 2009 में आया। 15वीं लोकसभा के गठन के बाद उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। इस तरह वे भारतीय संसद के इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला बनीं। 2009 से 2014 तक उन्होंने सदन का संचालन किया। उनका कार्यकाल उस दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसदीय संवाद और सदन की गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया। उनकी मृदुभाषी और सहज शैली ने उन्हें अलग पहचान दी।

मीरा कुमार का व्यक्तित्व राजनीति की सीमाओं से भी व्यापक रहा है। उन्हें साहित्य और कविता में रुचि रही है तथा भारतीय संस्कृति और परंपरा से उनका गहरा जुड़ाव रहा। महाकवि कालिदास की 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' उनकी प्रिय पुस्तकों में शामिल है। खेलों में भी उनकी रुचि रही और निशानेबाजी तथा घुड़सवारी से उनका जुड़ाव रहा। यही विविधताएं उनके व्यक्तित्व को संवेदनशील और बहुआयामी बनाती हैं। 2017 में मीरा कुमार को विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना साझा उम्मीदवार बनाया। यह उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रीय स्तर पर बनी उनकी स्वीकार्यता का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सकीं, लेकिन देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका नाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो चुका था।

मीरा कुमार की जीवन-यात्रा इस बात का उदाहरण है कि सार्वजनिक जीवन में विरासत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अपनी पहचान स्वयं के कर्मों से ही बनती है। राजनयिक से राजनेता और फिर लोकसभा अध्यक्ष तक का उनका सफर शिक्षा, अनुभव, संघर्ष और संयम का मेल है। उनकी सहजता और संसदीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में स्थान देती है।

पदक जीतने का माध्यम नहीं है खेल, खेल अनुशासन सिखाता है: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चम्पावत के स्व. कैलाश चन्द्र गहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर में 'खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026' का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट खिलाड़ी गहना महर को मशाल सौंपकर खेल महाकुम्भ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने पूर्ण अनुशासन, निष्पक्षता एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने की शपथ ली। खिलाड़ियों द्वारा योगासन एवं उत्तराखंड के पारंपरिक खेल 'मुर्गा झपट' का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल महाकुम्भ प्रदेश की प्रतिभाओं को गांव की मिट्टी से राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उचित मंच

और संसाधनों के अभाव में प्रदेश की कोई भी प्रतिभाशाली खेल प्रतिभा पीछे न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि खेल अनुशासन सिखाते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं और गिरकर फिर उठने का साहस देते हैं। खेल स्वस्थ शरीर के साथ मजबूत चरित्र और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार खेलों को उत्तराखंड के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का महत्वपूर्ण आधार मानकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष खेल महाकुम्भ को और अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। न्याय पंचायत स्तर से शुरू होकर विधानसभा, संसदीय एवं राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इस वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से खेल महाकुम्भ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के परिश्रम, प्रतिभा और उनके सपनों का सम्मान है।

गृहमंत्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की समीक्षा की

-अमित राय

जगत प्रवाह. सिलीगुड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सेना, बीएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ सहित अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई इस बैठक में, मल्टी-एजेंसी सेंटर (एमएसी) के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बने स्टैंडिंग फोकस ग्रुप (एसएफजी-एससी) ने अब तक हुई प्रगति और कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपनी सिफारिशों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। बैठक के दौरान, गृहमंत्री ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चल रही उन सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की, जो इसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने पीआईओ गतिविधियों, जनसांख्यिकीय बदलावों, घुसपैठ और सीमा से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए 'चतुष्कोणीय अप्रोच' के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया और सभी एजेंसियों

को इसे पूरी स्पिरिट के साथ लागू करने का निर्देश दिया। कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के महत्व पर जोर देते हुए, शाह ने वहां मौजूद सभी एजेंसियों को सभी लंबित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को उत्तर बंगाल में और सैनिक स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्तर बंगाल में सीनियर एनसीसी कैडेट्स की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम करने को भी कहा। साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की व्यवस्था को मजबूत करने का आग्रह किया।

मानव मूल्यों के पक्षधर श्रीकृष्ण

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष

प्राचीन संस्कृत साहित्य की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण दस अवतारों में एकमात्र ऐसे थे, जो सोलह कलाओं से निपुण पूर्णावतार थे। कृष्ण को लोक मान्यता प्रेम और मोह का अभिप्रेरक मानती हैं। इसीलिए मान्यता है कि कृष्ण के सम्मोहन में बंधी हुई गोपियां अपनी सुध-बुध और मर्यादाएं भूल जाया करती थीं। कृष्ण गोपियों को ही नहीं समूचे जनमानस को अपने अधीन कर लेने की अद्भुत व अकल्पनीय नेतृत्व क्षमता रखते थे। अतएव उन्होंने जड़ता के उन सब वर्तमान मूल्यों और परंपराओं पर कुठाराघात किया, जो स्वतंत्रता को बाधित करते हुए मानवता विरोधी थे। यहां तक कि जिस इंद्र को जल का देवता और तीनों लोकों का अधिपति माना जाता था, उन्हें भी मामूली ग्वाले कृष्ण ने चुनौती दी और उनकी पूजा को ब्रजमंडल में बंद करा दिया। वे कृष्ण ही थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के रण-प्रांगण में अर्जुन को आसक्ति मुक्त कर्म करने का उपदेश दिया। अर्थात संदेश था, आसक्ति रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।

जब कंस के आमंत्रण पर अक्रूर कृष्ण को लेने गोकुल आए तो कृष्ण के अनुराग में लिप्त गोप-गोपियों में हाहाकार मच गया। क्योंकि कंस की दुष्टता से सब परिचित थे और ग्यारह वर्षीय कृष्ण सबको नादान लगते थे। लेकिन कृष्ण ने आमंत्रण स्वीकार किया और निर्लिप्त भाव से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। जिस बांसुरी की धुन से कृष्ण गोपियों को लालायित किया करते थे, उस बंसुरी को भी गोपियों को दे गए। अपने बाल सखाओं और गोपियों को छोड़ते वक्त कृष्ण को भी दुख था, लेकिन वे कर्तव्य के दायित्व बोध से संचालित हो रहे थे। गोया, निर्लिप्त भाव का प्रगटीकरण आवश्यक था। यदि कृष्ण मोह के बंधन में बंधकर रह जाते तो कंस के दुराचारी शासन से बृजमंडल को मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात यहां के लोग परतंत्रता ही झेलते रहते। कृष्ण की इस निर्लिप्ता में संदेश अंतर्निहित है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए न केवल सचेत रहना चाहिए, अपितु जरूरत पड़ने पर क्रूरतम इरादों से भी संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना स्वतंत्रता न तो प्राप्त करना संभव है और न ही उसकी रक्षा करना संभव है। यहां कृष्ण यह भी संदेश देते हैं कि शासक कोई भी हो, समय कितना भी विपरीत हो, विजय हमेशा सत्य और धर्म की होती है।

जब कृष्ण का शिशु रूप में अवतरण हुआ तब उनके जन्म के साथ ही हत्या की प्रत्यक्ष भूमिका रच दी गई थी। उनके छह नवजात भ्राताओं की माता-पिता की खुली आँखों के सामने ही एक-एक कर हत्या कर दी गई। उनकी जान बचाने के लिए भी एक निर्दोष सद्यजात बालिका को बलि-वेदी की भेंट चढ़ना पड़ा। लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाद होता है। कारागार के एक-एक कर ताले टूटते चले जाते हैं। प्रहरी नींद के आगोश में आ जाते हैं। पिता वसुदेव कृष्ण को डलिया में रखकर निनाद करती यमुना को पार कर गोकुल में नंद-यशोदा के घर छोड़ आते हैं। यह कहानी इस बात कि प्रतीक है कि मानव-हितैषी सद्भावनाओं पर प्रतिबंध स्थाई नहीं रहते। शासक भले ही कितना ही शक्तिशाली हो एक दिन अन्यायरूपी बंधन के तालों को टूटना ही पड़ता है।

कृष्ण को आयु के अनुपात से कहीं ज्यादा सतर्कता, चैतन्यता और संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा! ऐसे विकट और विषाक्त परिवेश में अपनी, अपने समाज की प्राण रक्षा के लिए छल-कपट और लुका-छिपी के अनेक खेल, खेलने पड़े। यदि ये खेल कृष्ण नहीं खेलते तो क्या बच पाते ? विस्मय नहीं, कि जब लोकतंत्र से राजतंत्र की भिडंत होती है, तो जड़ हो चुकी स्थापित मान्यताओं के परिवर्तन की माँग उठती ही है। प्राण खतरे में डालकर कठोर संघर्ष करना ही पड़ता है। इतिहास साक्षी है, इन्हीं संकट और शत्रों से सामना करने वाले साहसी ही ईश्वर, नायक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं।

कृष्ण बाल जीवन से ही जीवनपर्यंत सामाजिक न्याय की स्थापना और असमानता को दूर करने की लड़ाई इंद्रदेव व कंस की राजसत्ता से लड़ते रहे। वे गरीब की चिंता करते हुए खेतीहर संस्कृति और दुग्ध क्रांति के माध्यम से ठेठ देशज अर्थ व्यवस्था की स्थापना और विस्तार में लगे रहे। सामारिक दृष्टि से उनका श्रेष्ठ योगदान भारतीय अखण्डता के लिए उल्लेखनीय है। इसीलिए कृष्ण के किसान और गौपालक कहीं भी फसल व गायों के क्रय-विक्रय के लिए मंडियों में पहुंचकर शोषणकारी व्यवस्थाओं के शिकार होते दिखाई नहीं देते? कृष्ण जड़ हो चुकी उस राज और देव सत्ता को भी चुनौती देते हैं, जो जन-विरोधी नीतियां अपनाकर लूट-तंत्र और अनाचार का हिस्सा बन गई थीं? भारतीय लोक के कृष्ण ऐसे परमार्थी थे, जो चरित्र भारतीय अवतारों के किसी अन्य पात्र में नहीं मिलता।

कृष्ण का पूरा जीवन समृद्धि के उन उपायों के विरूद्ध था, जिनका आधार लूट और शोषण रहा। शोषण से मुक्ति, समता व सामाजिक समरसता से मानव को सुखी और संपन्न बनाने के गुर गढ़ने में कृष्ण का चिंतन लगा रहा। इसीलिए कृष्ण जब चोरी करते हैं, स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराते हैं, खेल-खेल में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कालिया नाग का मान-मर्दन करते हैं तो उनकी ये सब चंचलताएं रूपी हरकतें अथवा संघर्ष उत्सवप्रिय हो जाते हैं। नकारात्मकता को भी उत्सवधर्मिता में बदल देने का गुरूमंत्र कृष्ण चरित्र के अलावा दुनिया के किसी अन्य इतिहास नायक के चरित्र में विद्यमान नहीं हैं?

भारतीय मिथकों में कृष्ण के अलावा कोई दूसरी ईश्वरीय शक्ति ऐसी नहीं है, जो राजसत्ता से ही नहीं, उस पारलौकिक सत्ता के प्रतिनिधि इन्द्र से विरोध ले सकती हो, जिसका जीवनदायी जल पर नियंत्रण था? यदि हम इन्द्र के चरित्र को देवतुल्य अथवा मिथक पात्र से परे मनुष्य रूप में देखें तो वे जल प्रबंधन के विशेषज्ञ थे। लेकिन कृष्ण ने रूढ़, भ्रष्ट व अनियमित हो चुकी उस देवसत्ता से विरोध लिया, जिस सत्ता ने इन्द्र को जल प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी और इन्द्र जल निकासी में पक्षपात बरतने लगे थे। किसान को तो समय पर जल चाहिए, अन्यथा फसल चौपट हो जाने का संकट उसका चैन हराम कर देता है। कृष्ण के नेतृत्व में कृषक और गौपालकों के हित में यह शायद दुनिया का पहला आंदोलन था, जिसके आगे प्रशासकीय प्रबंधन नतमस्तक हुआ और जल वर्षा की शुरूआत किसान हितों को दृष्टिगत रखते हुए शुरू हुई।

पुरुषवादी वर्चस्ववाद ने धर्म के आधार पर स्त्री का मिथकीकरण किया। इन्द्र जैसे कामी पुरूषों ने स्त्री को स्त्री होने की सजा उसके स्त्रीत्व को भंग करके दी। देवी अहिल्या के साथ छलपूर्वक किया गया दुराचार इसका शास्त्र सम्मत उदाहरण है। आज नारी नर के समान स्वतंत्रत और अधिकारों की मांग कर रही है, लेकिन कृष्ण ने तो औरत को पुरूष के बराबरी का दर्जा द्वापर युग में ही दे दिया था। राधा विवाहित थीं, लेकिन कृष्ण की मुखर दीवानी थी। ब्रज भूमि में स्त्री स्वतंत्रता का परचम कृष्ण ने फहराया। जब स्त्री चीर हरण (द्रोपदी प्रसंग) के अवसर आया तो कृष्ण ने चुनरी को अनंत लंबाई दी। स्त्री संरक्षण का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दुनिया के किसी अन्य साहित्य में नहीं है? इसीलिए वृंदावन में यमुना किनारे आज भी पेड़ से चुनरी बांधने की परंपरा है। जिससे आबरू संकट की घड़ी में कृष्ण रक्षा करें। सामाजिक जीवन में कृष्ण स्त्री स्वतंत्रता के इतने प्रबल समर्थक थे कि उन्होंने जब अपनी बहन सुभद्रा के मन में अर्जुन के प्रति अनुराग का अनुभव किया तो बड़े भाई बलराम की इच्छा के विरुद्ध सुभद्रा को अर्जुन से गंधर्व-विवाह कर लेने की अनुमति दी। यही नहीं, जब कृष्ण को रुकमणि का हरण करके विवाह कर लेने का संदेश मिला तो कृष्ण रुकमणि को भी योद्धाओं के बीच से हर लाए।

कृष्ण युद्ध कौशल के महारथी होने के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा संबंधी सामरिक महत्व के जानकार थे। इसलिए कृष्ण पूरब से पश्चिम अर्थात मणीपुर से द्वारका तक सत्ता विस्तार के साथ उसके संरक्षण में भी सफल रहे। मणीपुर की पर्वत श्रृंखलाओं पर और द्वारका के समुद्र तट पर कृष्ण ने सामरिक महत्व के अड्डे स्थापित किए, जिससे कालांतर में संभावित आक्रांताओं यवन, यूनानियों, हूणों, पठानों, तुर्कों, शकों और मुगलों से लोहा लिया जा सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे यही सीमांत प्रदेश आतंकवादी घुसपैठ और हिंसक वारदातों का हिस्सा बने हुए हैं। कृष्ण के इसी प्रभाव के चलते आज भी मणिपुर के मूल निवासी कृष्ण भक्त हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण की द्वारका से पूर्वोत्तर तक की यात्रा एक सांस्कृतिक यात्रा थी।

सही मायनों में बलराम और कृष्ण का मानव सभ्यता के विकास में अद्भुत योगदान है। बलराम के कंधों पर रखा हल इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। वहीं कृष्ण मानव सभ्यता व प्रगति के ऐसे प्रतिनिधि हैं, जो गायों के पालन से लेकर दूध व उसके उत्पादनों से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ग्रामीण व पशु आधारित अर्थव्यवस्था को गतिशीलता का वाहक बनाए रखने के कारण ही कृष्ण का नेतृत्व एक बड़ी उत्पादक जनसंख्या स्वीकारती रही। जबकि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में हमने कृष्ण के उस मूल्यवान योगदान को नकार दिया, जो किसान और कृषि के हित तथा गाय और दूध के व्यापार से जुड़ा था। बावजूद पूरे ब्रज-मण्डल और कृष्ण साहित्य में कहीं भी शोषणकारी व्यवस्था की प्रतीक मंडियों और उनके कर्णधार दलालों का जिक्र नहीं है। जीवित गाय को आहारी मांस में बदलने वाले कत्लखानों का जिक्र नहीं है। शोषण मुक्त इस अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, हमारे आधुनिक कथावाचक पंडितों और अर्थशास्त्रियों को इस गुर को समझने और समझाने की जरूरत है।

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

नेपाल बाढ़ की त्रासदी के व्यापक मायने

नेपाल में बीते महीने आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेपाल और तिब्बत सीमा पर आई इस विनाशकारी बाढ़ की वजह ग्लेशियर टूटना माना जा रहा है। इस आपदा ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में आ रहे बदलावों पर बहस का केंद्र में ला दिया है। इससे एक सवाल उठा है कि अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगी और धरती किस तरह से बदलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर बर्फ के पिघलने की संभावना नहीं है लेकिन फॉसिल फ्यूल जलाए जाने और लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक समय बाद ध्रुवों और पहाड़ों की चोटियों पर जमी सारी बर्फ पिघल भी सकती है। ऐसा होता है तो समुद्र का जल स्तर 216 फीट बढ़ जाएगा। इससे भारत और पड़ोसी देश भी अछूते नहीं रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की नई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों में भारत के मुंबई और कोलकाता समेत बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों के हमेशा के लिए पानी में डूबने और बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 के बीच वैश्विक समुद्र स्तर औसतन 4.7 मिली मीटर प्रतिवर्ष बढ़ा जबकि 2024 में यह

बढ़ोतरी 5.9 मिली मीटर रही। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना और महासागरों का गर्म होना इसके कारण बताए गए हैं । ग्लेशियर का पिघलना चिंता का विषय है। 1975 से 2000 के बीच जो ग्लेशियर हर साल दस इंच की दर से पिघल रहे थे, वे 2000 से हर साल बीस इंच की दर से पिघल रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिक तो वर्षों से चेता रहे हैं कि समूची दुनिया में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सच तो यह है कि हिमालय के तकरीब 650 से भी अधिक ग्लेशियर दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। कुछ साल पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ के वैज्ञानिकों के अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ था कि भारत, नेपाल, भूटान और चीन के लगभग दो हजार किमी भूभाग में फैले तकरीबन 650 से ज्यादा ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार पिघल रहे हैं। आई आई टी कानपुर के वैज्ञानिकों के अध्ययन ने उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाई है। पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर इंद्रेश्वर सेन ने बताया कि भारत में ग्लेशियर पिघलने की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा सिंधु और चिनाब जैसी नदियों को होगा। देश के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में लद्दाख के पेंगोंग इलाके में स्थित ग्लेशियरों के पिघलने से इस इलाके में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जिओ इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट के अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन तो अहम कारण है ही, चीन द्वारा पेंगोंग इलाके में झील पर पुल का निर्माण भी एक समस्या है जिसके कारण पारिस्थितिकी का संकट भयावह होता जा रहा है। इस संवेदनशील पर्वतीय इलाके में मानवीय गतिविधियों पर रोक जरूरी है। चिंता का सबब यही है कि ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने की खातिर इस संवेदनशील इलाके में ईंधन से चलने वाले वाहनों पर तत्काल रोक लगाई जाए। चीन द्वारा जो निर्माण किए जा रहे हैं उसपर रोक लगाना आवश्यक है। यदि इस हिमालयी क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां इसी रफ्तार से रही तो आने वाले सालों में हिमालय के एक तिहाई ग्लेशियरों पर मंडराते संकट को नकारा नहीं जा सकता। इससे 30 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इससे मानव जीवन और कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पेयजल संकट, बाढ़ तथा जानलेवा बीमारियों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से प्राथमिकता के आधार पर लड़ना जरूरी है।

क्षमा: कमजोरी नहीं, बड़प्पन की निशानी है

"कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, क्षमा करना तो ताकतवर की निशानी है।" यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का वह शक्तिशाली सूत्र है जो हमें साधारण से असाधारण बनाता है। क्षमा वह दिव्य शक्ति है जो टूटे हुए धागों को सिर्फ जोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। जैन समाज में पर्युषण के दौरान मनाया जाने वाला क्षमा पर्व संपूर्ण मानवता के लिये एक संदेश है कि मन का बोझ उतार फेंको, क्षमा मांगो-क्षमा करो और आगे बढ़ो। चलो मिलकर मैं को नहीं हम को जिताएं। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं, तो हमारा हृदय अहंकार के बोझ से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। और जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उसे नहीं, बल्कि स्वयं को घृणा के अंधकार से निकालकर प्रेम के प्रकाश में लाते हैं। यह केवल एक धार्मिक औपचारिकता नहीं, बल्कि स्वयं को अतीत की बेड़ियों से आजाद करने का सबसे बड़ा उत्सव है।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

जैन धर्म और क्षमा का अमर संदेश

जैन धर्म का कण-कण 'अहिंसा परमो धर्मः' के सिद्धांत पर आधारित है। यह केवल शारीरिक हिंसा की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक हिंसा, क्रोध, घृणा और द्वेष को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। शस्त्रों से पाई गई विजय अस्थायी होती है और अपने पीछे नफरत की खाई छोड़ जाती है। लेकिन क्षमा वह अस्त्र है जो शत्रुता को जड़ से समाप्त कर प्रेम के बीज अंकुरित करती है।

भगवान महावीर स्वामी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है:

"स्वयं पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी विजय है।" और क्षमा करना अपने क्रोध और अहंकार पर विजय पाने का सबसे सुंदर मार्ग है।

आत्मा के शुद्धिकरण का महापर्व

यह केवल एक त्योहार नहीं, यह आत्मा के मैल को धोकर उसे फिर से पवित्र बनाने का एक वार्षिक महायज्ञ है।

श्वेतांबर जैन समाजः पर्युषण पर्व आत्म-चिंतन और तपस्या का स्वर्णिम अवसर है। इसका शिखर "संवत्सरी" का दिन है, जब "मिच्छामी-दुक्कड़म" का दिव्य मंत्र हर दिशा में गूँजता है और दिलों को एक कर देता है। जो गत दिनों पूर्ण हुआ है।

दिगंबर जैन समाजः दशलक्षण पर्व (28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक) धर्म के दस लक्षणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। इसका समापन 8 सितंबर 2025 को "क्षमावाणी" दिवस के रूप में होता है, जो हमें याद दिलाता है कि समस्त धर्मों का अंतिम सार क्षमा ही है।

क्षमा पर्वः एक संदेश पूरी मानवता के लिए भले ही इस पर्व की जड़ें जैन धर्म में हैं, लेकिन इसकी शाखाएं पूरी मानवता को शीतल छाया देती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है किः गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना एक चुनाव है। क्षमा हमें सही चुनाव करने की आंतरिक शक्ति देती है। रिश्ते कांच के नहीं होते कि टूट जाएं, वे तो प्रेम और विश्वास की मिट्टी से बने होते हैं, जिन्हें क्षमा के जल से बार-बार संवारा जा सकता है। 'सॉरी' (Sorry) कहना एक शब्द हो सकता है, लेकिन "मिच्छामी-दुक्कड़म" कहना आत्मा की स्वीकृति है कि 'मेरे मन, वचन या कर्म से हुई किसी भी भूल के लिए मुझे क्षमा करें।' यह भाव हमें विनम्र और महान बनाता है।

हर सांस समाज के उत्थान के लिए समर्पित हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व विधायक स्व. बाबू रघुवीर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आकाशवाणी तिराहे पर पूर्व विधायक एवं नगर निगम परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय बाबू रघुवीर सिंह की प्रतिमा का रिमोट का बटन दबाकर अनावरण किया। साथ ही स्व. रघुवीर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। इस मौके पर केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर घोषणा की कि आकाशवाणी तिराहा अब स्वर्गीय श्री बाबू रघुवीर सिंह तिराहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि मनुष्य की प्रत्येक सांस की गिनती है। समय निरंतर गुजरता रहता है। हमें अपने जीवन में मिले समय का सदुपयोग कर समाज के उत्थान व जन कल्याण में अपनी सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्व. बाबू रघुवीर सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिक हों या किसान वर्ग, सभी के हितों और अधिकारों के लिए उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने जीवनभर समाज को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावुक है, क्योंकि बाबूजी को मैंने बाल्यावस्था से देखा था। सिंधिया ने कहा कि स्वर्गीय बाबू रघुवीर सिंह का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। वे

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर-घर जाकर उनके परिवारजनों की सेवा किया करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वर्गीय बाबू रघुवीर सिंह एक सच्चे श्रमिक नेता थे और उनका पूरा जीवन श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बीता। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय बाबू रघुवीर सिंह को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, नगर निगम सभापति मनोज तोमर, विधायक प्रीतम लोधी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि निशांत खरे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मंचासीन थे।

अब नेतृत्व की बारी है

नारी शक्ति वंदन

की जिम्मेदारी है

समृद्धि | सम्मान | सशक्तीकरण

महतारी वंदन
68 लाख माताओं- बहनों के खातों में अब तक ₹ 19,444 करोड़

महतारी सदन
महिला स्वरोजगार केंद्र के रूप में अब तक 137 महतारी सदनों का निर्माण

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
39.49 लाख से अधिक माताओं- बहनों की रसोई हुई धुंआ मुक्त

R.O. No. : 13992/ 1

रक्षाबंधन का त्योहार
विष्णु भैया का उपहार

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक। RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)